



नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

# पायनियर

www.dailypioneer.com



एक पेड़ मां के नाम  
जलवायु परिवर्तन  
को सटीक जवाब  
राष्ट्रीय-10

## डोनाल्ड ट्रंप ने दी मौत को मात

बटलर। एजेंसी

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर हुए हमले के तुरंत बाद रविवार को देशवासियों से एकजुटता और दृढ़ता का आह्वान किया। गोलीबारी में ट्रंप घायल हो गए लेकिन उनकी हालत ठीक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेनसिल्वेनिया के बटलर में शनिवार को चुनावी रैली में एक युवक ने गोलीचलाई और उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी, लेकिन वहाँ बाल-बाल बच गए। सहयोगियों के अनुसार उनकी हालत ठीक है। वहीं हमलावर को सीक्रेट एजेंसी के सदस्य ने मौके पर ही मार गिराया। यह घटना मिल्वाकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से दो दिन पहले हुई। इस सम्मेलन में ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं समेत दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने हमले की निंदा की है।

चुनावी रैली में हमले के बाद ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट टूथ पर लिखा, मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज आवाज सुनी, गोलीयाँ चलीं और तभी मुझे महसूस हुआ कि गोली मेरी त्वचा को चीरती हुई निकल गई। बहुत खून निकला। उन्होंने कहा, भगवान ने ही वह सब होने से रोक लिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। ट्रंप की पोस्ट के अनुसार, ऐसे समय में सबसे



राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद उनको सुरक्षित घेरे में नंग से ले जाते सुरक्षाकर्मी।

अधिक महत्वपूर्ण है कि हम एकजुट रहें और अमेरिकियों के तौर पर अपना मूल चरित्र बनाए रखें। हम मजबूत और दृढ़संकल्पित बने रहें और बुवाई को न जीते दें। एफबीआई ने रविवार को हमलावर की पहचान पेनसिल्वेनिया के बेथेल पार्क निवासी 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप

में की। उसके पास एक राइफल थी। सीक्रेट सर्विस के कर्मियों ने उसे मार गिराया। गोलीबारी की इस घटना में ट्रंप की रैली में मौजूद एक व्यक्ति की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गोली मारने के बाद से

अमेरिका के किसी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या की सबसे गंभीर कोशिश थी। हमले के बाद, पूर्व राष्ट्रपति को तुरंत मंच से बाहर ले जाया गया। ट्रंप ने भीड़ की ओर मुट्ठी बांध कर हाथ हवा में लहराया और कहा कि हम मुकाबला करेंगे। इसके बाद, उन्हें कार में

बिठाकर पिट्सबर्ग क्षेत्र के एक अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाते वक्त ट्रंप ने कहा, मुझे मेरे जूते ले लेने दीजिए। गोलीबारी की इस घटना में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की जांच हत्या के प्रयास

मामले के तौर पर की जा रही है। सीक्रेट सर्विस के एक सदस्य ने हमलावर को मार गिराया। संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने हमलावर की पहचान बेथेल पार्क के रहने वाले 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में की है। वह रिपब्लिकन के रूप में वोट करने के लिए पंजीकृत था। शूटर के पास जो एआर-15 था, वह मिलिट्री एम-16 का सेमी-ऑटोमैटिक स्विचिंग वर्जन है।

एफबीआई के विशेष एजेंट एवं पिट्सबर्ग कार्यालय के प्रभारी केविन रोजेक ने संवाददाताओं से कहा कि यह हैरानी की बात है कि बंदूकधारी कई गोलीयाँ चला पाने में कामयाब रहा। रोजेक ने कहा, आज शाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। पेनसिल्वेनिया राज्य पुलिस के जॉर्ज बिसेस ने कहा कि अधिकारियों को हथियार के संबंध में अंदाजा है लेकिन अभी जांच जारी है। ट्रंप पर हमले की घटना के करीब दो घंटे बाद बाइडन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अमेरिका में इस तरह की हिंसा पहले कभी नहीं सुनी। क्विड हाउस ने बताया कि ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में किस्मत आजमा रहे राष्ट्रपति जो बाइडन को हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने गोलीबारी के कई घंटे बाद ट्रंप से फोन पर बातचीत की। बाइडन ने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जवाब नहीं है। उन्होंने डेलवियर के रिहाबोध बीच पर स्थित अपने बीच



लखनऊ में भाजपा कार्यसमिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में हैं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, पार्टी नेता अशोक सिंह चौधरी, रमूति इरानी, अरुण सिंह और अन्य

## नियमों के तहत मनाएं जाएं धार्मिक उत्साव: योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि किसी भी तरह के समारोह या उत्सव को अधिकारियों द्वारा तय नियमों के तहत ही मनाया जाना चाहिए, अन्यथा जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसे किसी भी कार्यक्रम से से दूर और घर के अंदर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा भाजपा कार्यकर्ता जब विपक्ष में थे तो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष करते थे, अब जब सरकार में हैं तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वातावरण देख रहे हैं। याद कीजिए मुहरम के समय में सड़कें खाली हो जाती थीं और आज जब मुहरम होता है तो पता भी नहीं चलता। योगी ने कहा कि पहले ताजिया के नाम पर घर तोड़ दिए गए, पीपल के पेड़ काट दिए गए, सड़कों से तार

हटा दिए गए। आज कहा जा रहा है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटाई जाएगी। सरकार नियम बनाएगी, अगर त्यहार मनाया है तो नियमों के तहत मनाएं, नहीं तो घर बैठें। योगी ने लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। योगी की यह टिप्पणी राज्य और देश भर में मुहरम जुलूस के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। पिछले सप्ताह भी सीएम ने गोरखपुर दौरे के दौरान मुहरम के दौरान हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर रोक लगाने पर जोर दिया था और कहा था कि जुलूसों पर कड़ई गिराना रखी जानी चाहिए, जिन्हें लिखित अनुमति के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने मौजूदा परंपराओं (शेष पेज 9)



## मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ का जवान शहीद

पायनियर समाचार सेवा। इंपाल/गुवाहाटी

मणिपुर के ज़िरीबाम जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पुलिस के साथ संयुक्त पैट्रोलिंग टीम पर संधि उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक जवान शहीद हो गया जबकि, पुलिस के कमांडो घायल हो गए पुलिस ने बताया कि हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान बिहार के 43 वर्षीय अजय कुमार झा के रूप में की गई है। जवान के सिर में गोली लगी थी और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घायल पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह ने हमले की निंदा की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं आज ज़िरीबाम जिले में एक सशस्त्र समूह के हमले और उसमें सीआरपीएफ के एक जवान की हत्या की कड़ी निंदा करता हूँ। इस सशस्त्र समूह के कुकी उग्रवादी होने का संदेह है। उन्होंने कहा, कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं शहीद सैनिक के शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदन व्यक्त करता हूँ, साथ ही हमले के दौरान घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात को भी गांव में गोलीयाँ की आवाजें सुनाई दीं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रविवार के हमले के बाद मोंगबुंग में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में सुरक्षाकर्मियों का एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है।

## 46 साल बाद खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न मंडार

पायनियर समाचार सेवा। पुरी/नई दिल्ली

पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित खजाने रत्न भंडार को रविवार को 46 साल बाद फिर से खोला गया, ताकि कीमती सामानों की सूची बनाई जा सके और इसकी संरचना की मरम्मत की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इस मकसद से राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में प्रवेश किया और अनुष्ठान करने के बाद खजाने को फिर से खोल दिया गया। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान रत्न भंडार को फिर से खोलना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तत्कालीन सत्तारूढ़ बीजद पर चाबियों के गुम होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने वादा किया था कि अगर वह चुनाव जीती है तो खजाने को फिर से खोलने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर ओडिया अस्मिता की पहचान रखने वाले ओडिया समुदाय ने आगे बढ़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दोपहर 1.28 बजे सोशल मीडिया पर साझा



कर कहा गया, आपकी इच्छा पर जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार पहले ही खोल दिए गए थे। आज आपकी इच्छा पर 46 साल बाद एक बड़े उद्देश्य के लिए रत्न भंडार खोला गया। शुभ घड़ी में खजाने को फिर से खोलने का फैसला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में प्रवेश किया और अनुष्ठान करने के बाद रत्न भंडार पुनः खोला गया।



## कावेरी नदी मुद्दे ने पकड़ा तूल

कुमार चेल्लप्पन। चेन्नई

कावेरी नदी जल का मुद्दा एक बार फिर से तमिलनाडु में धान के कटोरे वाले क्षेत्र में कम समय में होने वाले कुखंड फसल के समय सामने आ गया है। कावेरी जल विनियमन समिति (केडब्ल्यूआरसी) ने वृहस्पतिवार को कर्नाटक सरकार से 12 जुलाई से 31 जुलाई तक तमिलनाडु को प्रतिदिन एक हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसीएफटी) पानी छोड़ने को कहा है ताकि तमिलनाडु के निचले तटवर्ती चार जिलों (तिरुवरूर, तंजावुर, नागपट्टिनम और तिरुचिरापल्ली) में कुखंड खेती का काम शुरू किया जा सके। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऊपरी तटवर्ती राज्य द्वारा 31 जुलाई से पहले तमिलनाडु को कोई भी पानी छोड़ने की संभावना (शेष पेज 9)

## फर्जी ई-नोटिस पर गृहमंत्रालय ने किया सतर्क

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई ने रविवार को कहा कि ईमेल पर किसी सरकारी कार्यालय से संदिग्ध ई-नोटिस मिलने पर लोगों को इसमें लिखे अधिकारियों के नाम की प्रामाणिकता की इंटरनेट पर जांच करनी चाहिए और संबन्धित विभाग को फोन करना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को किसी सरकारी ई-नोटिस की आइड में भेजे गए फर्जी ईमेल को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यह कोई टाग हो सकता है जो लोगों को साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। 14सी ने ऐसे ईमेल पर क्लिक करने या उनका जवाब देने से पहले जवाबी उपाय सुझाए हैं कि यह जांच करें कि क्या ईमेल किसी प्रामाणिक सरकारी वेबसाइट से आया है जिसके अंत में जीओवी डॉट इन है, ईमेल में नामित अधिकारियों के संबंध में इंटरनेट पर जानकारी खंगालें और प्राप्त ईमेल को सत्यापित करने के लिए संबंधित विभाग को फोन करें। इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईमेल उपयोगकर्ताओं को दिल्ली पुलिस साइबर अपराध और आर्थिक अपराध, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो



(सीईआईबी), खुफिया ब्यूरो और दिल्ली के साइबर प्रकोष्ठ के नाम, हस्ताक्षर, टिकट और लोगो वाले धोखाधड़ी के ईमेल के बारे में सचेत करते हुए एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया। चार जुलाई को जारी परामर्श के अनुसार, इन ईमेल के साथ संलग्न पत्र में ईमेल प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण, साइबर पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि टाग ऐसे फर्जी ईमेल भेजने के लिए अलग-अलग ईमेल पते का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहा गया है, ऐसे किसी भी ईमेल के प्राप्तकर्ता को इस धोखाधड़ी के प्रयास के बारे में पता होना चाहिए। आम जनता को सूचित किया जाता है कि संलग्नक के साथ ऐसे किसी भी ई-मेल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की सूचना निकटतम पुलिस थाने/साइबर पुलिस थाने को दी जा सकती है। गृह मंत्रालय और 14सी के रविवार को जारी परामर्श में कहा गया है कि ऐसे संदिग्ध ईमेल और अन्य प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के बारे में तुरंत साइबर अपराध की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराए या साइबर अपराध के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। साथ ही ऐसे किसी भी ईमेल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन में की जा सकती है। साइबर अपराधों से बचाव के लिए (शेष पेज 9)

## अल्काराज ने जोकोविच को हराकर चौथा ग्रैंडस्लैम खिताब जीता

एपी। लंदन

स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रविवार को यहाँ सर्वियाई स्टर नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 (4) से हराकर 21 साल की उम्र में लगातार दूसरा विम्बलडन और चौथा ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम किया। यह ऑल इंग्लैंड क्लब के घसियाले कोर्ट पर पिछले साल के फाइनल मैच का दोहराव था जिसमें अल्काराज ने पांच सेट में जोकोविच को हराया था। सैंटर कोर्ट पर रविवार को खेला गया फाइनल अल्काराज के लिए काफी आसान रहा जिसमें दर्शकों में केंसर का उपचार कर रही ब्रिटेन की वेल्स की

राजकुमारी केट मिडलटन भी मौजूद थीं। अल्काराज सिर्फ तीसरे सेट में 5-4 पर जीत के लिए सर्विस करते समय तीन मैच प्वाइंट बरकरार रखते समय लड़खड़ाए। पर उन्होंने खुद को संभाला और पिछले महीने फ्रेंच ओपन में मिली जीत के बाद लगातार दूसरी ग्रैंडस्लैम ट्रॉफी जीती। स्पेन के इस खिलाड़ी ने 2022 अमेरिकी ओपन में किशोर के तौर पर अपना पहला स्लैम खिताब जीता था। किसी भी खिलाड़ी ने 22 साल का होने से पहले उनसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम खिताब नहीं जीते हैं। इससे मेजर फाइनल्स में उनका रिकॉर्ड 4-0 हो गया। वहीं 37 वर्षीय जोकोविच अपने आठवें विम्बलडन और 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब से चूक गए। वह सर्जरी हुए घुटने



पर पट्टी लगाए थे। तीन जून को रोलांड गैरो में उनके घुटने में चोट लगी थी और दो दिन बाद ही उनकी सर्जरी हुई थी। करीब छह हफ्ते बाद भी जोकोविच रविवार को फॉर्म में नहीं दिखे। जोकोविच के दोनों बच्चे गेस्ट बॉक्स में थे, उन्होंने कहा, पहले दो सेट में मेरे खेल का स्तर अच्छा नहीं था। आज सब कुछ उसके हक में था। मैंने उसे पछाड़ने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तीसरे सेट में अल्काराज 5-4 से आगे थे। वह 40-लव से आगे था पर मौका उनके हाथ से निकल गया। वह डबल फॉल्ट करके अपना पहला चैम्पियनशिप प्वाइंट गंवा बैठे। इससे उनकी पांच गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ जिसके कारण यह गेम

जोकोविच ने अपने नाम किया। अल्काराज का एक बैकहैंड, एक फोर्हैंड वॉली, एक फोर्हैंड, एक और फोर्हैंड खराब रहा। जोकोविच ने पूरे मैच में सिर्फ यहीं अल्काराज की सर्विस तोड़ी। फिर स्कोर फाइव-ऑल हो गया जिससे अल्काराज परेशान दिखे और जोकोविच की वापसी की उम्मीद जगी। लेकिन टाइमआउट में अल्काराज ने अपना चौथा मैच प्वाइंट हासिल किया और जितना हो सके उतना कूल रहे। और जल्द ही वह अपने कोच जुआन कार्लोस फेरेरो और अन्य लोगों को गले लगाते के लिए स्टैंड पर चढ़ते दिखे मुकाबला बॉर्डर के अंदर खत्म हुआ। शुरुआती गेम से उतार चढ़ाव भरे लंबे मुकाबले की उम्मीद थी। लेकिन

पहले दो सेट अल्काराज ने 6-2 से जीत लिए जिससे तीसरा सेट मैच का सबसे प्रतिस्पर्धी रहा। जोकोविच ने पहले सेट में डबल फॉल्ट से दो ब्रेक प्वाइंट गंवा दिए। फिर दूसरे सेट की शुरुआत में नेट में वॉली लगाई और अंत में डबल-फॉल्ट से इसे गंवा बैठे। युवा अल्काराज ने अपने से उम्रदार जोकोविच के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाया जिसमें उन्होंने ऐसे शॉट खेल जिन्हें कोई आजमा भी नहीं सकता था। फाइनल से दो दिन पहले जोकोविच ने अल्काराज की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था, मैं उसमें और खुद में बहुत समानताएं देखता हूँ और यह कोर्ट से सामंजस्य बिटाने की काबिलियत के आधार पर कह रहा हूँ।









## जो बाइडेन

### क्षमता पर सवाल

जो बाइडेन की क्षमता पर सवालों के साथ उन पर हमले तेज हो रहे हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी को कठोर निर्णय लेना होगा कि जो बाइडेन उसके राष्ट्रपति उम्मीदवार बने रहें या उनका विकल्प पेश किया जाए। दोनों स्थितियां कठिन हैं और उनके सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष हैं। बाइडेन की आयु व उनकी क्षमताओं के प्रदर्शन से पार्टी को 'प्लान बी' पर विचार करना होगा। लेकिन डेमोक्रेटों के लिए समय तेजी से बीतता जा रहा है और यही स्थिति विकल्पों की है। हालांकि, इस प्रकरण की शुरुआत काफी पहले हो गई थी, पर 'राष्ट्रपति बहस' एक प्रकार से 'ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका' सिद्ध हुई जिसमें बाइडेन का प्रदर्शन बहुत खराब था। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बाइडेन के पक्ष में मजबूत तर्क हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धियों का लंबा समय देखा है जिनमें व्यापक ढांचागत संरचना विधेयक, महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन पहलें तथा जीवन्त कोविड-19 टीकाकरण अभियान शामिल हैं। बाइडेन प्रशासन जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों से निपटने में सफल हुआ है। उसने अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने में सफलता पाई है तथा खासकर चीन और रूस के खिलाफ गठबंधनों को मजबूत किया है। उनके मध्यमगी दृष्टिकोण का लक्ष्य अत्यधिक विभाजित राष्ट्र को एकजुट करना था। इसके लिए उन्होंने प्रगतिशील व मध्यमगी डेमोक्रेटों तथा निर्दलीयों व रिपब्लिकनों से भी अपील की। लेकिन बाइडेन की आयु और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिन्ता बनी हुई है। 81 साल की आयु में वे अमेरिकी इतिहास के सबसे वयोवृद्ध राष्ट्रपति हैं। उनकी क्षमताओं तथा मानसिक सतर्कता पर राजनीतिक विरोधी तथा मीडिया



अनुमान लगाते रहे हैं। जनमत सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि मतदाताओं का बड़ा हिस्सा उनकी क्षमताओं से असहज तथा चार वर्ष का एक और कार्यकाल देने पर दुविधाग्रस्त है। इसके साथ ही कुछ मुद्दों से निपटने के उनके तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान से वापसी तथा वर्तमान आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं। इसके लिए उनके दोनों पक्षों के राजनेताओं की आलोचना झेलनी पड़ी है। इन विवादों से अफवाहों को बल मिला है कि क्या डेमोक्रेटों को 2024 में विजय दिलाने के लिए बाइडेन सर्वोत्तम उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनाव को अब केवल चार महीने बचे हैं और डेमोक्रेटों द्वारा उनका विकल्प तलाशना कठिन है। ऐसे में 25वां संशोधन लागू करना भी आत्यन्तिक व असंभव लगता है जो सेवा करने में अक्षम राष्ट्रपति को हटाने का प्राविधान करता है। इसके संभावित राजनीतिक नतीजों के साथ ही 'अक्षमता' के स्पष्ट व अविवादित प्रमाण होने चाहिए। इस प्रकार यह रास्ता जोखिम भरा है। यदि डेमोक्रेट विकल्प तलाशने का निर्णय करें तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में अनेक हाई-प्रोफाइल नेता सामने आएंगे। वर्तमान उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस सर्वाधिक संभावित पसंद हो सकती हैं। पहली महिला, पहली अश्वेत व पहली दक्षिण एशियाई उप-राष्ट्रपति के रूप में उनका प्रस्ताव बहुत मजबूत है, पर उनके नेतृत्व तथा नीतिगत प्रभावशीलता पर गहरे सवाल हैं। परिवहन सचिव व साउथ बेंड, इंडियाना के पूर्व मेयर पीट बुटीगेग एक और उम्मीदवार हो सकते हैं। वे युवा, स्पष्ट वक्ता तथा नीतिगत समझदारी वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ ही प्रगतिशील नीतियों के पैरोकार व कैलीफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसन ने भी राजनीतिक चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है। इस प्रकार वर्तमान समय में डेमोक्रेट भारी दुविधा के शिकार हैं। अंततः निर्णय बाइडेन की प्रभावी नेतृत्व क्षमता तथा पुनः चुनाव जीतने की संभावना पर होगा।

# तालिबानों से महिलाओं का संघर्ष

तालिबान अधिकारियों के इनकार के बावजूद अफगान महिलायें अपने प्रति गंभीर व अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ उठ कर खड़ी हो रही हैं। विडंबना है कि विश्व जनमत इस उत्पीड़न पर खामोश है।



**हिरण्यमय कालेंकर**  
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

तालिबान अधिकारियों के इनकार के बावजूद अफगान महिलायें अपने प्रति गंभीर व अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ उठ कर खड़ी हो रही हैं। इसके अनेक प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। 'द गार्जियन' में जाहरा जोया, क्रिस मैक्ग्रील, खुदाबाद पोलादी, एनी केली व टाम लेविट की रिपोर्ट 6 जुलाई, 2024 को प्रकाशित हुई। इसका शीर्षक 'वीडियो एपियर्स टु शो गैंग-रेप आफ अफगान वीमेन इन तालिबानी जेल' है, यानी इस वीडियो में संभवतः तालिबानी जेल में अफगान महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। इससे अफगानिस्तान में जघन्य स्थिति का पता चलता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो 'द गार्जियन' तथा अफगानिस्तान में महिला संबंधी मुद्दों पर खबरें देने वाले आनलाइन मीडिया 'रूखसाना मीडिया' द्वारा यह वीडियो देखा गया।

इसमें एक युवा महिला और मानवाधिकार कार्यकर्ता से तालिबान जेल में सशस्त्र लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार व अत्याचार दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि महिला से अपने कपड़े उतारने को कहा गया और उसके बाद दो लोगों द्वारा उससे कई बार बलात्कार किया गया। उसे नंगी खड़े देखा गया, उसकी आवाज लड़खड़ा रही है और हमलों के दौरान उसे पहचाना जा सकता है। 'द गार्जियन' और 'रूखसाना मीडिया' में महिला को यह कहते दिखाया गया है कि उसे तालिबान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया तथा तालिबानों की जेल में उससे कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया। यह वीडियो उसे अफगानिस्तान से भाग जाने को बाध देने का प्रयास है। इस धमकी दी गई कि यदि उसने सार्वजनिक रूप से 'इस्लामी अमीरात' के खिलाफ कुछ बोला तो यह वीडियो उसके परिवार को दिखाया जाएगा तथा इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न, पिटाई तथा अत्याचारों के अन्य उदाहरण



भी दिए गए हैं। इनमें न केवल तालिबानों द्वारा महिला-अधिकारियों के दमन के विजली के झटके देने, बल्कि युवा महिलाओं और किशोरियों द्वारा हिजाब अफगान महिलाओं के लिए अत्यधिक अपमानजनक व खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि हिरासत से 'अफगान महिलाओं पर बहुत भारी दाग लग जाता है जिससे उन पर खतरा और बढ़ जाता है।' महिलाओं के खिलाफ तालिबान के हमले 1996-2001 के बीच चले उनके पहले शासनकाल की याद दिलाते हैं जो उनके वर्तमान दूसरे शासनकाल में भी जारी हैं। बलात्कार और यौन उत्पीड़न ऐसे अत्याचारों का हिस्सा हैं।

इसकी शुरुआत सितंबर, 2021 में उस समय हुई जब तालिबान ने काबुल में महिला मामलों के मंत्रालय का बोर्ड हटा दिया और उसके स्थान पर 'मिनिस्ट्री फार प्रमोशन आफ वर्चु ऑड प्रिवेंशन आफ वाइस' का बोर्ड लगा दिया। अफगानिस्तान की सत्ता में पहली बार आए तालिबानों के शासनकाल में मनमाने व कठोर उत्पीड़न के लिए उनकी काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी। सरकार की आदिमकालीन सोच वाली घोषणाओं के चलते उन्होंने महिलाओं के प्रति अत्यधिक कठोरता बरती थी। वर्तमान समय में भी महिलाओं के खिलाफ अनेक कठोर कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को एक पुरुष संरक्षक के बिना 70

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि तथा यूएनएएमए की प्रमुख रोजा ओटुनबायेवा के हवाले से लिखा है कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई तथा शारीरिक हिंसा 'खासकर अफगान महिलाओं के लिए अत्यधिक अपमानजनक व खतरनाक है।' उन्होंने कहा है कि हिरासत से 'अफगान महिलाओं पर बहुत भारी दाग लग जाता है जिससे उन पर खतरा और बढ़ जाता है।' महिलाओं के खिलाफ तालिबान के हमले 1996-2001 के बीच चले उनके पहले शासनकाल की याद दिलाते हैं जो उनके वर्तमान दूसरे शासनकाल में भी जारी हैं। बलात्कार और यौन उत्पीड़न ऐसे अत्याचारों का हिस्सा हैं।

इसकी शुरुआत सितंबर, 2021 में उस समय हुई जब तालिबान ने काबुल में महिला मामलों के मंत्रालय का बोर्ड हटा दिया और उसके स्थान पर 'मिनिस्ट्री फार प्रमोशन आफ वर्चु ऑड प्रिवेंशन आफ वाइस' का बोर्ड लगा दिया। अफगानिस्तान की सत्ता में पहली बार आए तालिबानों के शासनकाल में मनमाने व कठोर उत्पीड़न के लिए उनकी काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी। सरकार की आदिमकालीन सोच वाली घोषणाओं के चलते उन्होंने महिलाओं के प्रति अत्यधिक कठोरता बरती थी। वर्तमान समय में भी महिलाओं के खिलाफ अनेक कठोर कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को एक पुरुष संरक्षक के बिना 70

किलोमीटर से अधिक यात्रा पर प्रतिबंध है जो उनका पति या 'महरम' हो। 'महरम' का अर्थ नजदीकी रक्त संबंधी है, जैसे पिता, बेटा, भाई, बाबा, परबाबा, ऐसा भतीजा जिससे विवाह प्रतिबंधित हो और जिसकी उपस्थिति में उसे हिजाब पहनने की जरूरत न हो। महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर 'समुचित' हिजाब तथा ऐसे ढीलेढाले काले कपड़े पहनने चाहिए जिनसे उनका शरीर और चेहरे पूरी तरह ढक जाएं। इसके लिए उनके पुरुष रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है जिनको अपना कर्तव्य पालन न करने पर दंड भुगतना पड़ता है। महिलाओं को प्रार्थमिक स्तर के बाद शिक्षा तथा हर प्रकार के रोजगार से वंचित किया गया है। सबसे बुरी बात है कि 23 मार्च, 2024 को अफगानिस्तान के राज्य टेलीवीजन पर प्रसारित एक मौखिक संदेश में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्ला अब्दुजादद को दोष लगाया गया है कि वह शर्त पर भाग लेने को तैयार हुआ था कि आयोजकों की ओर से कोई महिला सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तालिबानों की यह शर्त मान लेने की मानवाधिकार संगठनों से व्यापक रूप से निन्दा की थी। उनका यह आरोप था कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य देशों द्वारा तालिबानों की यह शर्त मान लेने का अर्थ उनको महिला-अधिकारों को और कुचलने का अवसर देना होगा।

समय उन्होंने यही सब किया था। ऐसे में यह देख कर अत्यधिक आश्चर्य होता है कि बाकी दुनिया अफगान महिलाओं के साथ हो रहे इस घोर उत्पीड़न व मानवाधिकार उल्लंघन पर एकदम चुप है। दुनिया के अनेक जिम्मेदार देश और उनके राजनेता तालिबानों द्वारा अफगान महिलाओं पर ढाए जाने वाले ऐसे अत्याचारों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं। इस संबंध में सारी दुनिया में स्वयं को लोकतंत्र के रक्षक की तरह पेश करने वाले पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की चुप्पी और अधिक चिन्ताजनक है। लोकतांत्रिक देश तालिबानों के खिलाफ इस मामले में किसी प्रभावी कार्रवाई के मामले पर भी पूरी तरह खामोश हैं। विडंबना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे जुड़ी संस्थायें भी अफगान महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न पर सक्रिय नहीं दिख रही हैं, जबकि इस बारे में 'द गार्जियन' तथा 'रूखसाना मीडिया' की स्पष्ट वीडियो आधारित प्रमाणित रिपोर्ट के अलावा अन्य अनेकानेक प्रमाण सारी दुनिया के समक्ष मौजूद हैं।

हाल ही में दोहा और कतर में 25 देशों के राजदूतों का वैश्विक सम्मेलन हुआ। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर तालिबान के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। यह अपने क्रिस्म का तीसरा वैश्विक सम्मेलन था। हालांकि, तालिबान ने पहले दो सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था, पर इस सम्मेलन में भी वह इस शर्त पर भाग लेने को तैयार हुआ था कि आयोजकों की ओर से कोई महिला सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तालिबानों की यह शर्त मान लेने की मानवाधिकार संगठनों से व्यापक रूप से निन्दा की थी। उनका यह आरोप था कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य देशों द्वारा तालिबानों की यह शर्त मान लेने का अर्थ उनको महिला-अधिकारों को और कुचलने का अवसर देना होगा।

मानवाधिकार संगठनों की यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा लगता है कि मानवाधिकारों और महिला अधिकारों की बड़ी-बड़ी बातें करने वालों को अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं व लड़कियों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों और दमन की जरा भी चिन्ता नहीं है।

# मोदी-पुतिन मुलाकात से रिश्तों में आई नई जान



**पारुल चंद्रा**  
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

यह धारणा बढ़ रही थी कि भारत और रूस के बीच संबंधों में गति कम हो रही है, यहां तक कि ठहराव आ रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर-स्तरीय बैठक द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने में मदद करेगी। भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दो वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित 22वें शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने का संकल्प लिया। शिखर सम्मेलन के परिणामों ने मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए नई दिल्ली के इरादे को व्यक्त किया, भले ही रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने और उसके बाद उसके देश पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पुतिन को पश्चिमी देशों द्वारा व्यापक रूप से बंदनाम किया गया हो।

पुतिन के रूस-यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने के कारण, जो अब अपने तीसरे वर्ष में है, शिखर-स्तरीय बैठकें पीछे छूट गई थीं। पिछली शिखर वार्ता दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में हुई थी। शिखर वार्ता में दोनों पक्षों की ओर से न केवल 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को पुनर्जीवित करने की उत्सुकता दिखाई गई, बल्कि आर्थिक सहयोग को भी संबंधों का आधार बनाया गया। यह एक अलग संयुक्त वक्तव्य में परिलक्षित हुआ, जिसमें आर्थिक सहयोग के लिए नौ प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा बताई गई, जिसमें 2030 के लिए 100 बिलियन डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया। मोदी-पुतिन शिखर वार्ता में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को दुनिया के सबसे खुली अर्थव्यवस्था को गले लगाते हुए देखकर निराशा और शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका व्यक्त किया, लेकिन इससे नई दिल्ली के बीच के साथ घनिष्ठ संबंधों को नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है। भारत ने भले ही आक्रमण की निंदा न की हो, लेकिन मोदी ने पुतिन से कहा कि युद्ध के मैदान में शांति नहीं है जबकि उन्होंने बातचीत की आवश्यकता पर भारत की स्थिति को दोहराया। वाशिंगटन ने मोदी-पुतिन की मुलाकात पर अपनी



नाराजगी भी जताई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे मॉस्को के साथ उसके संबंधों पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की रणनीतिक जरूरतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। बेशक, इनमें से एक रूस-चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां हैं। रूस के साथ नजदीकी संबंधों पर जोर देने से मॉस्को की वाशिंगटन के प्रति नई दिल्ली के झुकाव को लेकर चिंताएं भी दूर होंगी। भारत अब तक दो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहा है और उसे ऐसा करना जारी रखना चाहिए। भारत रूस को समय-परीक्षित भरोसेमंद

साझेदार के रूप में देखा है। पश्चिमी दुनिया प्रतिबंधों से प्रभावित रूस को यूक्रेन युद्ध के मामले में अलग-थलग रखना चाहेगी, लेकिन भारत का व्यापक और गहरे आर्थिक संबंधों के लिए प्रयास उसकी अपनी रणनीतिक जरूरतों को दर्शाता है। प्रतिबंधों के बावजूद भारत की रूसी तेल खरीद न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है। रूस से कच्चे तेल का आयात 2021 में 2.5 मिलियन टन से बढ़कर 2023 में 90 मिलियन टन हो गया है, भारत को यह स्पष्ट है कि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों द्वारा

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। रूस से उर्वरक आयात भी भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रूसी तेल आयात ने द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों को 65.70 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने में मदद की है। लेकिन जबकि भारतीय आयात 61.44 बिलियन डॉलर का था, इसके नियतों का हिस्सा मात्र 4.26 बिलियन डॉलर था। रियायती दरों पर रूसी तेल आयात करने में खुश होने के बावजूद, नई दिल्ली को रूस के साथ व्यापार की टोकरी को चौड़ा करके इस व्यापार असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता होगी। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात और विद्युत मशीनरी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को खत्म करने और यूरोशियन आर्थिक संघ-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की संभावना पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के इरादे की गंभीरता को दर्शाता है। भारत और ईएईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पूर्ण वार्ता शुरू करने की प्रेरणा से भी व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलना चाहिए।

कनेक्टिविटी भी दोनों पक्षों के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। इसका मतलब होगा भारतीय सामानों के लिए यूरोशियाई बाजारों तक पहुंच। हालांकि, प्रस्तावित (अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन) गलियारा अभी भी वास्तविकता बनने से बहुत दूर है। जबकि चेन्नई-व्लादिवास्तोक सेबूची गलियारा स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच फिर से रुचि है, जिसे पहली बार 2019 में पेश किया गया था, यह भी देखा जाना बाकी है कि यह फलीभूत होगा या नहीं। शिखर सम्मेलन ने निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया, जो भारत के सुरक्षा प्रतिमान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, भले ही नई दिल्ली अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे अन्य देशों की ओर रुख करके विविधता लाने के निरंतर प्रयास कर रहा हो। भारत निस्संदेह यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी सैन्य हार्डवेयर और पुर्जों की आपूर्ति में देरी पर अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगा। मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन ने भले ही पश्चिम को नाराज कर दिया हो, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नई दिल्ली तब तक अपना काम जारी रखेगी जब तक कि यह उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करता रहे।

## आप की बात

### बिगडैल नाबालिग

देश में रसूखदारों के बिगडैल शहजादों के ही अधिकतर हिट एन रन मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे बिगडैल नाबालिग कर्हें पुरुषाण पर सोये लोगों पर नशे में गाड़ी चढ़ा देते हैं तो कर्हें अन्य दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसी दर्दनाक घटनाएं अक्सर मीडिया व सोशल मीडिया में आने लगी हैं। दूसरी ओर लव जिहाद के गंभीर व दर्दनाक किस्से भी मॉस्को की सुर्खी बन रहे हैं। कभी किसी लड़की के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं तो कर्हें बोरियों में भरकर नदी में बहा दिए जाते हैं। समाज और सरकार को ऐसे मामले रोकने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश के कानूनविदों व पुलिस को मिलकर

नाबालिगों द्वारा किए अपराधों को रोकने पर विचार करना चाहिए। यह सच है कि नाबालिगों व पहली बार अपराध करने वालों को वयस्कता व आदतन अपराधियों जितनी सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन बचपन से ही बच्चों में समाज के प्रति जिम्मेदारी तथा अपराध और दंड से भय करना सिखाया जाना चाहिए। गंभीर अपराधों में नाबालिग को वयस्क की तरह सजा देने का अधिकार भी यथासंभव न्यायालय के विवेकाधिकार तथा स्थितियों के विश्लेषण पर छोड़ने से नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। यह कदम जरूरी हो गया है।

### शूटिंग में दुर्घटनायें

फ़िक्म व टेलीविजन के इतिहास में शूटिंग के दौरान दुर्घटनाओं के कारण मौतें होती रही हैं। 1980 से 1990 तक स्टंट के दौरान 37 मौतें हुईं। इनमें से 24 मौतें हेलीकॉप्टर उपयोग संबंधी थीं। भारतीय फ़िक्म उद्योग में भी ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इंडियन 2 की शूटिंग में एक विशाल क्रेन गिरने से तीन तकनीशियनों की मौत हो गई, जबकि अभिनेता कमल हासन, काजल अग्रवाल और निर्देशक शनमुगम शंकर बच गए। 2004 में खाकी के सेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन के पैर में जीप की टक्कर से फ्रैक्चर हो गया था। 1980 के दशक में कुली के फ़िक्मांकन के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे। इसी तरह की एक दुर्घटना में 2021 में न्यू मैक्सिको में फ़िक्म शूटिंग के दौरान हेलिना हैचिन्स की गोली लगने से मौत हो गयी थी। गोली अभिनेता एलेक बाल्डविन के हाथों से चली थी। जबकि शूटिंग के दौरान नियम ये है कि बन्दूक असली होती है मगर उसके अंदर गोली नकली होनी चाहिए। अब सबूतों के अभाव में बाल्डविन को बरी कर दिया गया है। फिल्मों व टेलीवीजन शूटिंगों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं और खतरनाक मामलों में प्रशिक्षित लोगों का प्रयोग होता है।

### प्रशासन की जिम्मेदारी

प्रशिक्षु आईएसएस को के प्रयासों और निर्देशों के बावजूद केन्द्र व राज्य की अनेक जन-कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तथा उनमें भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। गांवों में शौचालय निर्माण व पीएम आवास बनाने की अगली किशतों तथा मनरेगा की बकाया धनराशि न मिलने की शिकायतें भी आ रही हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी जनता की शिकायतें दूर करना भी है। जनता तथा सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के बीच नियमित संवाद से भी प्रशासन की जिम्मेदारी व जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।

### स्वागत योग्य फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भी अब गुजारा भत्ता उनके पति से सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत दिलाने का फैसला दिया है। यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस को याद रखते हुए ये निर्णय दिया है जिसमें इसका प्रावधान था। लेकिन राजीव गंझका की सरकार ने 1986 में बनाए कानून से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निष्प्रभावी कर दिया था। अब 1986 का वह कानून धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना भी

स्वागत योग्य है कि गुजारा भत्ता कोई खैरात नहीं है बल्कि तलाकशुदा महिला का मौलिक अधिकार है। विडंबना है कि अनेक कट्टरपंथी मौलाना इसे शरीयत में दखलंदाजी कह रहे हैं, जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम-बहुल देशों में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है। कई मुस्लिम देशों में पुरुषों को बिना अदालती फैसले तलाक देने पर प्रतिबंध है तथा वे एक से फैसला निष्प्रभावी कर दिया था। कर सकते हैं। भारतीय मुसलमानों को भी अब दकियानूसी सोच छोड़ कर आगे बढ़ना चाहिए।

# उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा: सूर्य प्रताप शाही

**तीन दिवसीय आम महोत्सव का समापन**

● **निर्यातकों को 20 लाख रुपये तक मार्ग व्यय में अनुदान की सुविधा दी जा रही है: दिनेश प्रताप सिंह**

**पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ**

**कृषि मंत्री** सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को तीन दिवसीय आम महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुये कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में उद्यान विभाग नई ऊंचाई छू रहा है। प्रदेश का आम आज देश नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलने, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। निर्यात को बढ़ाने हेतु विदेशों में पैक हाउस, ट्रीटमेंट सेंटर एवं आधुनिक टैरिस्टिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। पैक हाउस के माध्यम से किसानों के उत्पादों का ट्रीटमेंट, पैकिंग और सुरक्षित रखते हुए विदेशी बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों में प्रदेश के किसानों के उत्पादों की डिमांड ज्यादा हो इसके लिए हम अपने उत्पादों की देखरेख और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। आम महोत्सव जैसे आयोजन किसानों को उनके उत्पादों में सुधार करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिस प्रकार वर्ष 2023 में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यान विभाग एवं प्रगतिशील बागवानी का प्रतिनिधि मण्डल आस्को, रूस भेजा गया था उसी प्रकार इस वर्ष भी उद्यान



प्रतिनिधि मण्डल यूक्रेन भेजा जायेगा। उन्होंने किसानों के आय में वृद्धि के लिये अधिक से अधिक निर्यात पर जोर दिया। रूस में आयोजित आमरस-2023 कार्यक्रम की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि रूस में प्रदेश के आम की निरंतर मांग बनी हुई है। उन्होंने योगी सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु दी जाने वाली सुविधाओं व अनुदान के द्वारा प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक का पुरस्कार तथा आम की विभिन्न किस्मों में 09 पुरस्कार प्रदान किये गये। महोत्सव के अवसर पर सर्वोच्च 17 पुरस्कार श्री इकबाल अहमद, मलिहाबाद, लखनऊ तथा एस0सी0 शुक्ला, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा 13 पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

तीन दिनों तक चलने वाले इस आम महोत्सव में 7 श्रेणियों के 58 ज्यों में आम की विभिन्न प्रजातियाँ तथा उनके प्रसंस्कृत उत्पादों की प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। जिसमें आम की लगभग 800 प्रजातियों के 2660 नमूने प्रदर्शित किये गये। महोत्सव में जहाँ एक ओर आम की विभिन्न प्रजातियों में 1224 प्रतिभागियों द्वारा 2340 नमूने प्रदर्शित किये गये, वहीं दूसरी ओर आम की संरक्षित पदार्थ वर्ग में 90 प्रतिभागियों द्वारा 310 नमूने प्रदर्शित किये गये। आम पकवान के 03 प्रतिभागियों द्वारा 10 नमूने प्रदर्शित किये गये। केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, उद्यान विभाग के सहायक निदेशक, बस्ती, प्रयागराज, झांसी

(बर्कआसागर) एवं लखनऊ (मलिहाबाद) में स्थापित औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रगतिशील बागवानी के द्वारा अपने-अपने संस्थानों/बागों में उगायी जाने वाली प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों ने भी प्रतिभाग करते हुये अपने प्रदर्श प्रदर्शित किये। प्रदेश में आम की सुप्रसिद्ध दशहरी, लंगड़ा, चँसा, गौरजीत, लखनऊ सफेदा, रटौल, आझपाली प्रजातियों के साथ-साथ टॉमी एटकिस, सन्सेशन, अरुणिका आदि रंगीन प्रजातियाँ भी आकर्षण का केन्द्र रही। आम महोत्सव-2024 के अन्तिम दिवस में किसानों, उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, छात्रों के समक्ष खाद्य प्रसंस्करण के महत्व एवं रोजगार सृजन में योगदान विषय पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में विषय विशेषज्ञों द्वारा डेटिंग, फूड सेफ्टी, मूल्य सम्वन्ध, पैकेजिंग पर, अर्धप्रसंस्करण, आम के उत्पाद प्रसंस्करण एवं प्रोडक्ट टैरिस्टिंग विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। समापन अवसर पर विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रायबरेली, श्रीमती वन्दना चौधरी, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण वीएल मीणा, कृषि निदेशक एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कथनी और करनी एक दूसरे से विपरीत है। लोकरसभा चुनाव में पराजय से भाजपा को खराबहट है। इनके अपने सहयोगी और समर्थक किनारा करने लगे हैं। जनता में भाजपा की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। भाजपा सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया। किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग गरीबों में निराशा है। बीजेपी ने राजनीति को व्यापार बना दिया है। महंगाई बढ़कर सबको ठगा है। भाजपा ने किसी को नहीं छोड़ा। भाजपा ने अपनी गलत नीतियों से दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, कर्मचारियों, व्यापारियों महिलाओं सभी को संकट में डाला। लोगों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता समाजवादियों की तरफ आश भरो निगाहों से देख रही है। जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रही है। समाजवादी पार्टी जनता के दुःख-दर्द और उसकी जरूरतों को समझती है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। हमेशा जनता के हित में फैसले लिए है। प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर जो भरोसा जताया है पार्टी उसे और मजबूत करेगी।

## बेनकाब हो चुकी है भाजपा: अखिलेश

**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जनता के बीच बेनकाब हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भ्रष्टाचार चरम पर है भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं को अराजकता और गुण्डाई से गरीब पीड़ित है। किसान, नौजवान संकट में है। महंगाई, बेरोजगारी से हर वर्ग त्राहिले कर रहा है। जनता भाजपा के झूठ और लूट को समझ गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान विरोधी कार्य किया है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। संवैधानिक समस्थानों का दुरुपयोग कर भाजपा बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती थी, पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीना, नौकरियों में घोटाला किया। लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है, विधानसभा चुनाव 2027 के चुनाव में भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा।



जनता भाजपा को कुशासन, भेदभाव और नफरत की राजनीति से ऊब गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक बनाया गया भ्रमजाल टूट चुका है। भाजपा की

## भाजपा की सरकार पूरी तरह से नाकाम : अजय राय

**लखनऊ।** प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय रविवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी पहुंचे। जहाँ उन्होंने जनपद की विधानसभा पतिया के ब्लॉक विजुआ के ग्राम एलनगंज में हाल ही में इलाज व संसाधनों के अभाव के कारण इंटर की छात्रा शिवानी की हुई मृत्यु व उसके पार्थिव शरीर को लेकर उनके भाइयों को घर के लिए पाँच किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जिसका सज़ान लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार जनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने बताया की दिवंगत शिवानी बीमार चल रही थी और डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया था। बाढ़ के कारण यातायात प्रभावित था, किसी प्रकार की सरकारी सहायता भी उपलब्ध नहीं थी। नतीजा शिवानी की इलाज के आभाव में मृत्यु हो गई और दुर्दशा इतनी की भाइयों को शिवानी के शव को कंधे पर उठाकर ही घर के लिये चलना पड़ा। गांव में ना तो सड़क सुविधा

है और प्राथमिक इलाज के लिए भी 20-22 किलोमीटर जाना पड़ता है। हवाई स्कूल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी पहुंचे। जहाँ उन्होंने जनपद की विधानसभा पतिया के ब्लॉक विजुआ के ग्राम एलनगंज में हाल ही में इलाज व संसाधनों के अभाव के कारण इंटर की छात्रा शिवानी की हुई मृत्यु व उसके पार्थिव शरीर को लेकर उनके भाइयों को घर के लिए पाँच किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जिसका सज़ान लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार जनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने बताया की दिवंगत शिवानी बीमार चल रही थी और डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया था। बाढ़ के कारण यातायात प्रभावित था, किसी प्रकार की सरकारी सहायता भी उपलब्ध नहीं थी। नतीजा शिवानी की इलाज के आभाव में मृत्यु हो गई और दुर्दशा इतनी की भाइयों को शिवानी के शव को कंधे पर उठाकर ही घर के लिये चलना पड़ा। गांव में ना तो सड़क सुविधा

## डिफेंस कॉरिडोर में वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही योगी सरकार

● **यूपीडा की देख-रेख में 537 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य निर्माणाधीन**

**लखनऊ।** देश को रक्षा उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में आकार ले रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में योगी सरकार वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इसके लिए सरकार को ओर साढ़े 9 सौ करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इसके अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर में सड़क, बिजली, पानी, सीवर और सुरक्षा के उच्चकोटि के प्रबंध किये जा रहे हैं। प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड हैं, जिनमें से 5 नोड के लिए ये रकम तय की गई है। यूपीडा के अधिकारियों को ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अबतक करीब 187 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो गये हैं। वहीं 537 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हैं। यूपीडा की ओर से कराए जा रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ और चित्रकूट नोड में 941.19 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसमें अलीगढ़ नोड के लिए 122 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जा रहे हैं। यहां 32 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हो चुके हैं, 16

**लखनऊ नोड में 82 करोड़ के कार्य निर्माणाधीन**  
वहीं लखनऊ नोड की बात करें तो यहां 166 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हो रहे हैं, जिसमें से 14 करोड़ से अधिक के कार्य हो चुके हैं, जबकि 82 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हैं। यहां पर 13 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का टेंडर हो चुका है, जबकि 56 करोड़ रुपये से अधिक आगामी कार्यों के लिए रखे गये हैं। इसी प्रकार चित्रकूट नोड में 71 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जाऐं। यहां पर 39 लाख रुपये के कार्य निर्माणाधीन हैं, जबकि 10 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का टेंडर हो चुका है। यहां 61 करोड़ रुपये से अधिक आगामी कार्यों के लिए रखे गये हैं। बता दें कि रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश के दो डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में तेजी से आकार ले रहा है। राज्य में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी हैं। योगी सरकार के प्रयासों से इन नोड्स में करीब 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ हो गया है, जिससे 40 हजार युवाओं के लिए सीधे-सीधे रोजगार का सृजन होगा। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार यूपीडीआईसी के लिए अबतक 154 एमओयू हो चुके हैं। अबतक 16 सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है, जिसमें से सात सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि 42 औद्योगिक समूहों को आवंटित हो गई है। इन 42 उद्योग समूहों की ओर से करीब आठ हजार करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है।

37 करोड़ से अधिक के कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 61 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हैं। वहीं 13 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा तकरीबन 10 करोड़ रुपये आगामी कार्यों के लिए रखा गया है। इसी प्रकार कानपुर नोड के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जाऐं। यहां भी 32 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हो चुके हैं, 16 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हैं, जबकि 13 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य के टेंडर हो चुके हैं। ऐसे ही झांसी के लिए सर्वाधिक 517 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हो रहे हैं। इसमें 102 करोड़ से अधिक के कार्य हो चुके हैं, 376 करोड़ से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हैं, जबकि 37 करोड़ से अधिक आगामी कार्यों के लिए रखे गये हैं।

## वर्चुअल मूल्यांकन से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएगी सरकार

● **एनकास पाने वाली सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर आमजन को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का इलाज**

**पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ**



**योगी सरकार** आयुष्मान आरोग्य मंत्रियों के नेशनल क्वैलिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनकास) प्रमाण पत्र के लिए वर्चुअल मूल्यांकन से मूल्यांकन करने जा रही है। अभी तक एनकास की टीम स्वयं जाकर इन स्वास्थ्य इकाइयों का भौतिक सत्यापन करती थीं। इस प्रक्रिया में काफी वकत लगता था। योगी सरकार के इस फैसले से एनकास प्रमाणित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए एनकास व कायाकल्प सर्टिफिकेट के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 1.70 लाख से

अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में 17 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 'आयुष्मान भारता, गुणवत्ता स्वास्थ्य' लॉन्च किया है, उसमें एक बड़ा बदलाव यह भी है। दो अन्य पहलु भी की गई हैं, जिनमें इंटरनेट पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के लिए डैशबोर्ड और फूड वेंडर्स के लिए स्मार्ट फूड लाइसेंस देना शामिल है। इसके अलावा एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए एनकास व कायाकल्प सर्टिफिकेट के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 1.70 लाख से

सर्टिफिकेशन के लिए वर्चुअल मूल्यांकन और डैशबोर्ड की शुरुआत करने का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक आम लोगों की पहुंच को बढ़ाना तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। वर्चुअल विजिट में रोगियों, कर्मचारियों और समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की जा सकेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिकी जेवल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, अपर निदेशक व सीएमओ को पत्र जारी किया है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जनपद में हर महीने 10 से 20 चिकित्सा इकाइयों का वर्चुअल मूल्यांकन जरूर कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 50 प्रतिशत स्वास्थ्य इकाइयों को वर्ष 2025 तक और वर्ष 2026 तक प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एनकास प्रमाणित कराने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह साराहीन फैसला है। इससे दूरस्थ इलाकों में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का भी मूल्यांकन हो सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉ. निशत कुमार जायसवाल ने बताया कि अब तक प्रदेश की 275 चिकित्सा इकाइयों एनकास सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुकी हैं, जिसमें 56 जनपद स्तरीय, 42 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं एवं अगले तीन महीने में इतनी ही एवं इकाइयों को इसके दायरे में लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार केवल उन्हीं स्वास्थ्य इकाइयों को यह प्रमाण-पत्र प्रदान करती है जो मानक के अनुरार मरीजों का उपचार और देखभाल करती हैं। जो स्वास्थ्य इकाइयों एनकास प्रमाणित होंगी वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उन इकाइयों में सुविधाएं भी बढ़ी मिलेंगी। उन्होंने बताया कि एनकास प्रमाण पत्र देने वाली संस्था नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसेर्च सेंटर (एनएचएसआरसी) को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आईएसक्यूएईएफ एफ्रीडिएशन मिला है। इसका मतलब है कि एनकास न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रमाण पत्र है बल्कि एनएचएसआरसी अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाली संस्था भी है।

## भयावह रूप ले चुकी है महंगाई: रीबू श्रीवास्तव

**पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ**

**समाजवादी महिला सभा** की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश के कृषि मंत्री का यह बयान कि 100 रुपये किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं हैं भयावह रूप ले चुकी महंगाई और उससे परेशान जनता का मजाक उड़ाने जैसा है। यह गरीब जनता के प्रति उनकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है।

रीबू ने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदैव सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का विरोध सड़क से संसद तक किया है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता ने उन पर अपना भरोसा जताते हुए समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी नम्बर की ताकतपूर्ण पार्टी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई है। रीबू श्रीवास्तव के अनुसार समाजवादी महिला सभा कृषि मंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान का विरोध करते हुए प्रदेश के माध्यम से कृषि मंत्री से मांग करती है या तो दाल की कीमत 100 रुपये करें या फिर अपनी मांगों के लिए देश की जनता से माफी मांगें।

**सपा लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नामित**

**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वीकृति से समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव द्वारा श्री संदीप चौधरी निवासी बस्ती को समाजवादी लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नामित किया गया है।

## बाढ़ को लेकर सरकार ने बरती सतर्कता, ग्राउंड जीरो पर खुद भी पहुंचे सीएम योगी

● **हवाई सर्वे के साथ ही नाव से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया मुआयना**  
● **प्रदेश में 10 दिनों के अंदर 11 हजार से अधिक लोगों को किया रेस्क्यू**  
● **बाढ़ की दृष्टि से प्रदेश के 24 जिले अतिसंवेदनशील और 16 जिले संवेदनशील**

**लखनऊ।** बाढ़ को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले से ही की गई तैयारियों ने जनता को बड़े मुकाम से बचा लिया है। प्रदेश में मानसून से पहले अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में की गई तैयारियां का नतीजा है कि हजारों लोगों की जान बचाने में सरकार को सफलता मिली है। पिछले दस दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही असर रहा कि अफसर भी ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिये, वहीं मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वास्तुस्थिति से अवगत होते रहे। एक तरफ जहाँ उन्होंने हवाई सर्वे के माध्यम से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया तो वहीं नाव से भी प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किट वितरित की और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। आपदा के दौरान अर्पणों को खोने वालों के परिजनों को सीएम ने सहायता धनराशि का चेक प्रदान किया। श्रावस्ती के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में 11 लोगों का रेस्क्यू करने वाले 7 लोगों को सीएम ने प्रशस्ति पत्र सौंप व एक लाख रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। योगी सरकार ने प्रदेश में मानसून के दस्तक देने से पहले ही बाढ़ की तैयारियां शुरू कर दी थीं। सीएम योगी ने अतिसंवेदनशील 24 और संवेदनशील 16 जिलों में आपदा की स्थिति बनने से पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गयीं थीं। इसको लेकर सीएम योगी



ने जून के दूसरे सप्ताह से ही अधिकारियों के साथ बैठकों का दौरा शुरू कर दिया था। सीएम ने राहत कार्यों से जुड़े अधिकारियों को शासनस्तर से लेकर फील्ड में तैनात अधिकारियों को पूरी ताकत से काम करने के निर्देश दिये थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर राहत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने राहत कार्यों के दौरान छोटी-छोटी कमियों को दूर करने के निर्देश दिये। इतना ही नहीं वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप अधिकारियों ने फील्ड में

पिछले दस दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11962 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। 21,239 से अधिक मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 804 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं, जिसमें कुल 1,365 लोग रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1178 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। इन क्षेत्रों में 914 नाव चलाई जा रही हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को 23,93,41 से अधिक लंच पैकेट और 7,345 से अधिक खाद्यान्न सामग्री भी वितरित की गयी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए 12 एनडीआरएफ, 9 एसडीआरएफ, 23 पीएसी और 1 एसएस्वी को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आर्मी एयरफोर्स एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी से निरंतर समन्वय बना हुआ है। पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नाव द्वारा तथा 170 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। वहीं श्रावस्ती में 213 मवेशियों और 2280 व्यक्तियों का

रेस्क्यू किया गया। बाढ़ शरणालयों में रहने वाले प्रत्येक शरणार्थी के लिए पके हुए स्क्व और पीस्टिक भोजन की प्रशिक्षण से अतिव्यवस्था की गई है। यहां स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम गठित की गई है। पेय जल, औषधियों और ओआरएस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। शरणार्थियों की व्यवस्था के लिए विस्तारों की भी व्यवस्था की गई है। शरणालयों में राति के लिए समुचित प्रकाश व्यवस्था भी की गई है। यहां आने वाले शिशुओं के लिए दूध व पुष्टाहार की भी व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं के लिये स्वच्छता संबंधी डिगनिटी किट की व्यवस्था की गई है। उनकी प्राइवैसी को भी सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक शरणालय में शरणार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वर्षा व बाढ़ के कारण विपैले जंतुओं की सक्रियता के दृष्टिगत ब्लॉक स्तर पर एंटीवेनम, औषधियों व इंजेक्शनों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पशुओं को उंचे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और उनके लिये चारा-पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।









